

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काज़ी मकदूम शफीउद्दीन

बीड में दोषियों के खिलाफ मक़ोका के तहत कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक का तबादला मुख्यमंत्री की घोषणा

परभणी मामले की न्यायिक जांच और बीड में एसआईटी जांच मृतकों के परिवारों को 10 लाख की सहायता

जमीर काज़ी

नागपुर, 20 दिसंबर : बीड और परभणी जिलों में हुई हिंसा और पुलिस अत्याचारों ने पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैला दिया है। नागपुर में जारी शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा छाया रहा, जहां सभी दलों के विधायकों ने पिछले चार दिनों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक बड़ा ऐलान किया।

बीड जिले के हत्या मामले में न्यायिक जांच और एसआईटी के माध्यम से दोहरी जांच होगी। परभणी मामले में न्यायिक जांच की जाएगी। इसके साथ ही बीड में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख और परभणी में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीड मामले की न्यायिक और एसआईटी जांच के साथ ही बीड के पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल का तत्काल तबादला किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने परभणी के पुलिस निरीक्षक अशोक घोरबंद को निर्लंबित करने की घोषणा की और यह जांच की जाएगी कि क्या उन्होंने घटना के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया। विधानसभा में बीड और परभणी की घटनाओं



पर हुई संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "परभणी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संविधान का अपमान, सभी भारतीयों का अपमान है, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परभणी की घटना एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ने की थी, जो मेडिकल रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। इस मामले में सभी राजनीतिक दल तनाव कम करने की कोशिश करेंगे।" परभणी की घटनाओं पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हिंदू-दलित दंगा नहीं था, बल्कि सामान्य हिंदू समाज मोर्चा द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर

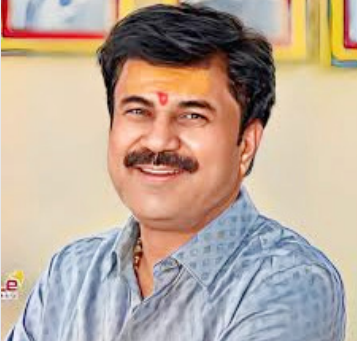


आधारित सर्वदलीय आंदोलन था। हालांकि, परभणी में हुई तोड़फोड़ से दुकानों, वाहनों और सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने बीड में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की और कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीड में निवेश करने वाली अवाडा ग्रीन एनर्जी कंपनी के मामले में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने कंपनी का काम अपने पास लेने या फिरौती की मांग की थी। बीड मामले के मास्टरमाइंड के खिलाफ मक़ोका के तहत कार्रवाई की जाएगी।

धनंजय मुंडे और वाल्मीकि को बचाने की कोशिश: विपक्ष का गंभीर आरोप

नागपुर : बीड और परभणी में हुई घटनाओं ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को हिला दिया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे जवाब देने से बचते हुए अपने मंत्री धनंजय मुंडे और आरोपी वाल्मीकि कराड को बचाने की कोशिश की। विवाद बढ़ गया जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया, जिससे नाराज होकर विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया।

विधान भवन की सीढ़ियों पर संवाददाताओं से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नितिन राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।



नितिन राउत ने कहा, “परभणी मामले पर मुख्यमंत्री का बयान पूरी तरह झूठ है। पुलिस द्वारा दलित आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के वीडियो उपलब्ध हैं, फिर भी मुख्यमंत्री ने पुलिस का बचाव किया। बीड मामले में भी उन्होंने ऐसा ही किया। हम जवाब देना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने का मौका नहीं दिया।”

जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया, “मुख्यमंत्री ने सब कुछ साफ होते हुए भी

गोलमोल बातें कीं। इससे स्पष्ट होता है कि वे अपने मंत्री धनंजय मुंडे और उनके साथी वाल्मीकि कराड को बचा रहे हैं। वाल्मीकि एक सीरियल किलर है, और मुख्यमंत्री के बयान ने इस मामले में उनकी और मुंडे की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। लेकिन हम सड़कों पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ेंगे।”

आदित्य ठाकरे ने कहा, “मुख्यमंत्री के बयान से यह स्पष्ट है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। महाराष्ट्र को बचाने के लिए हमारा संघर्ष चलता रहेगा।” यहां तक कि भाजपा के बीड विधायक सुरेश धस ने भी चिंता व्यक्त की और कहा, “मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें सामने आकर इन आरोपों का जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि वे चुप बैठे रहें।”

सगाई में ही शादी संपन्न: समाज के लिए नई मिसाल

अशफाक इनामदार की बेटी का सगाई में ही निकाह



बीड : नगर परिषद के पूर्व सभापति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नेता अशफाक इनामदार की बेटी और केज के हेडमास्टर वहाजुद्दीन अंसारी के बेटे डॉ. आकिब अंसारी की सगाई की रस्म अमन लॉन्स में आयोजित की गई थी। लेकिन समारोह के दौरान रिश्तेदारों और पटेल समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि सगाई के दौरान ही शादी कर दी जाए। दोनों परिवारों ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महंगाई के इस दौर में, जहां आम लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार की शादी ने अनावश्यक खर्च और संसाधनों की बचत में मदद की। दोनों परिवारों ने, इनामदार समुदाय के सदस्यों के साथ

मिलकर, सगाई की रस्म में शादी करके समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पहल की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिला अध्यक्ष जनाब मौलाना साबिर रशीदी ने शादी से संबंधित इस्लामी नियमों की व्याख्या की, और बीड शहर के काजी, सय्यद फजलुल्लाह ने खुतबा निकाह पढ़ाया। इस आदर्श शादी समारोह को सफल बनाने में पूर्व उपमहापौर और एनसीपी नेता फारुक पटेल, पूर्व उपमहापौर मोइन मास्टर, अलहाज जेदी शाह, और पूर्व पंचायत समिति सदस्य हाजी सादिक फारूकी मामा ने विशेष प्रयास किए। इस समारोह में पूर्व विधायक

अमर सिंह पंडित, पूर्व विधायक सैयद सलीम, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक निगम के सदस्य शेख तैयब भाई, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी, एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शफी भाऊ खूरशीद, आलम, जैतुल्लाह खान, इंजीनियर सादिक इनामदार और अन्य ने भाग लिया। उन्होंने दूल्हा-दुल्हन और उनके परिवारों को बधाई दी और शुभकामनाएं दीं। प्रमुख उपस्थित लोगों में दूल्हे के पिता काजी वहाजुद्दीन, दुल्हन के पिता अशफाक इनामदार, अवेज इनामदार, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, समाजसेवी, राजनीतिक नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्य शामिल थे।

भारत जोड़ो यात्रा में शामिल शहरी नक्सली संगठनों की सूची

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की लिखित मांग

विशेष संवाददाता

मुंबई : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राज्य और लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले तथा शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले कई संगठनों ने हिस्सा लिया, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लगाया। इसके जवाब में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखकर इन शहरी नक्सली संगठनों और उनके प्रमुखों की सूची की मांग की है। इस पत्र में पटोले ने कहा कि प्रगतिशील महाराष्ट्र में विभिन्न सामाजिक संगठन कई वर्षों से जनता की भलाई, विशेष रूप से राज्य के गरीब और आम नागरिकों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन राज्य और देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय हैं। कई सामाजिक संगठनों के साथ-साथ बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। ऐसे संगठनों को नक्सली कहना बेहद अनुचित है।

जमीर काज़ी

नागपुर: कल्याण की एक हाउसिंग सोसायटी में मराठी निवासियों पर हुए हमले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधान परिषद में यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई मराठी लोगों की है और किसी भी स्थिति में उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कल्याण की योगीधाम सोसायटी में एक मराठी परिवार पर एमटीडीसी के अधिकारी अखिलेश शुक्ला द्वारा किए गए हमले की घटना ने आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। यह मामला विधान परिषद के नियम 289

के तहत सदस्य एडवोकेट अनिल परब द्वारा उठाया गया। चर्चा में शशिकांत शिंदे, भाई जगताप और सचिन अहिर जैसे सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा का उत्तर देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि अखिलेश शुक्ला और उनकी पत्नी ने झगड़े के दौरान मराठी निवासियों का अपमान किया। इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और शुक्ला, जो एमटीडीसी के कर्मचारी हैं, को निर्लंबित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आगे कहा, “महाराष्ट्र और मुंबई मराठी लोगों की है। चूंकि मुंबई वित्तीय राजधानी है, देशभर से प्रतिभाएं यहां आती हैं और शांति से रहती हैं। उत्तर प्रदेश से आए कई लोग न केवल धाराप्रवाह मराठी बोलते हैं बल्कि

डॉ. आंबेडकर के अपमान के खिलाफ संविधान चौक से विधान भवन तक MVA का प्रदर्शन

विशेष प्रतिनिधि

नागपुर, 19 दिसंबर:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के कथित अपमान के खिलाफ महाविकास आघाड़ी (MVA) के विधायकों ने गुरुवार को नागपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संविधान चौक से शुरू होकर विधान भवन की सीढ़ियों तक गया, जिसमें शाह और भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की शुरुआत MVA के विधायकों ने संविधान चौक स्थित डॉ. आंबेडकर की पूर्णकृति प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर की। बाबासाहेब की तस्वीरें लेकर और नारे लगाते हुए सभी विधायक विधान भवन

पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने "बाबासाहेब का ये अपमान नहीं सहेंगा हिंदुस्तान" और "जय भीम, जय भीम" जैसे बुलंद नारे लगाए। **भाजपा का महापुरुषों का अपमान** भाजपा की आलोचना करते हुए विजय वडेटीवार ने कहा, "चुनाव से पहले और बाद में अपने महापुरुष और देवताओं को बदलना भाजपा का फैशन बन गया है। भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने भारत में समानता का स्वर्ग बनाया। यही कारण है कि हम आंबेडकर का नाम लेते हैं और लेते रहेंगे। संविधान निर्माता बाबासाहेब आंबेडकर, जिन्होंने आम लोगों को उनके अधिकार और न्याय दिया,

का अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा।" प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान किया है। यह केवल आंबेडकर का ही नहीं, बल्कि संविधान और देश के नागरिकों का भी अपमान है। वडेटीवार ने सवाल उठाया, "देश का हर नागरिक जानता है कि डॉ. आंबेडकर ने देश के लिए क्या किया। बाबासाहेब ने समाज के हर वर्ग को न्याय दिया। अगर हमें अपमान महसूस होता है, तो क्या नीतीश कुमार, रामदास आठवले और भाजपा के अन्य सहयोगी ऐसा महसूस नहीं करते? उन्हें भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए।

किसी भी स्थिति में मराठी लोगों पर अन्याय नहीं होगा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मराठी त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाती हैं।" सीएम फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपने जीवन के तरीके, जिसमें भोजन की आदतें भी शामिल हैं, चुनने की स्वतंत्रता दी है। किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भेदभाव या उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को सख्ती से निपटारा जाएगा। उन्होंने कहा, "देश की विविधता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मराठी होने पर हमें गर्व है और इस गर्व को चोट पहुंचाने का कोई भी प्रयास सहन नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की

जाएगी।" **कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कार्रवाई होगी: अजीत पवार** हमले और अन्याय की घटना को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधान सभा में कहा, "महाराष्ट्र शिवाजी, शाहू, फुले और आंबेडकर की भूमि है। यहां अगर कोई मराठी लोगों के साथ अन्याय करता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" योगीधाम सोसायटी में मराठी व्यक्ति पर हमले और अन्याय का मामला ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने 'पॉइंट ऑफ़ इंफ़ॉर्मेशन' के माध्यम से विधानसभा में उठाया।

